

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी संख्या - 1002551 वर्ष 2006

राज कुमार

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त लखनऊ और 2 अन्य

....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: विजय कुमार पांडे, पीवी चौधरी
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पीवी चौधरी और प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
2. 01.12.2025 की कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। 26.11.2025 की आख्या के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को जारी किया गया पंजीकृत डाक सूचना का अपरिदत्त लिफाफा वापस नहीं मिला है और न ही आज तक कोई वकालतनामा दायर किया गया है। क्योंकि सूचना 2006 में जारी किया गया था, यानी 19 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और किसी ने वकालतनामा दायर नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए सूचना पर्याप्त माने जाते हैं।
3. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 07.04.2006 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में निहित है।
4. मामले की तथ्यात्मक आव्यूह यह है कि यह विवाद दसाऊ (जिन्हें राम दास भी कहा जाता है) के वंशजों से जुड़ा है, जिनके दो बेटे थे - रघु नंदन और भजन। रघु नंदन के छह बेटे हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राज कुमार (याचिकाकर्ता), शिव कुमार, राम आसरे, रामेश्वर, ओम प्रकाश और शिव प्रकाश। भजन का कोई बेटा नहीं था, उनकी विधवा जीवित हैं।

5. "विवाद वाली ज़मीन" में पाँच प्लॉट (103, 105, 118, 146, और 149) हैं, जिनकी कुल ज़मीन 0.47 एकड़ है। यह ज़मीन करिहारा गाँव, तहसील लालगंज, ज़िला रायबरेली में है। ग्राम पंचायत ने इन प्लॉट को भजन को लीज़ पर देने का प्रस्ताव पास किया। हालाँकि लीज़ भजन बेटे दसाऊ के लिए थी, लेकिन प्रस्ताव में गलती से उसे "भजन बेटा राम दास" लिख दिया गया।

6. भजन ने उपप्रभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) के सामने अपने पिता के नाम में सुधार के लिए आवेदन किया।

22 अप्रैल, 1990 को कानूनगो/राजस्व निरीक्षक की जांच के बाद, खतौनी (1395एफ से 1400एफ) में एक पृष्ठांकन किया गया, जिसमें साफ़ किया गया कि भजन के पिता का नाम सही में दसाऊ था। इस प्रविष्टि को राज्य या गाँव सभा ने सालों तक बिना किसी चुनौती के जारी रखा।

7. 28 जून, 1996 को भजन ने अपने दो भतीजों - ओम प्रकाश और शिव प्रकाश के नाम पर एक वसीयत बनाई। इसके कुछ समय बाद भजन की मौत हो गई, जिसके बाद भतीजों ने वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया। 9 दिसंबर, 1996 को तहसीलदार ने वसीयत को रद्द कर दिया और उसकी जगह भजन के सभी भतीजों (याचिकाकर्ता सहित) के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिए।

8. 7 अप्रैल, 2005 को नौ साल बाद, याचिकाकर्ता (राज कुमार) ने प्रविष्टि को चुनौती दिया, यह आरोप लगाते हुए कि 1990 का सुधार ग़लत था और ज़मीन गाँव सभा को वापस मिलनी चाहिए क्योंकि "भजन, राम दास का बेटा" माना जाता है कि बिना वसीयत के मर गया था। 30 दिसंबर, 2005 को उपप्रभागीय अधिकारी ने प्रविष्टि को तुरंत हटा दिया (अनुलग्नक 3)। 9 मार्च, 2006 को दूसरे भाइयों (शिव कुमार, वगैरह) की आवेदन पर, उपप्रभागीय अधिकारी ने हटाने का आदेश वापस ले लिया और सही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नई सुनवाई की तारीख तय की।

9. 7 अप्रैल, 2006 को जब इन कामों के बारे में एक पुनरीक्षण लंबित था था, तो विद्वान आयुक्त ने न सिर्फ़ पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर यह निर्देश दिया कि ज़मीन दूसरे "पात्र व्यक्तियों" को फिर से आवंटित की जाए (अनुलग्नक 1)।

10. याचिकाकर्ता का कहना है कि आयुक्त के आदेश ने सही सुनवाई के अधिकार को असल में कम कर दिया है। उपप्रभागीय अधिकारी के प्रविष्टि की वैधता के बारे में चल रहे फैसले को पूरा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने से पहले पुनः आवंटन का निर्देश देकर, आयुक्त ने सही अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया और पक्षों को सुनवाई का मौका नहीं दिया। इसलिए, यह रिट याचिका इस न्यायालय के सामने पेश की गई है।

11. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि जब उन्होंने पुनरीक्षण को खारिज करने के लिए आवेदन दिया, तो विवादित ज़मीन को फिर से आवंटन करने का आदेश पास करने के लिए अभिलेख में कोई तथ्य नहीं था। उन्होंने कहा कि 07.04.2006 का आदेश याचिकाकर्ता को सूचना और सुनवाई का मौका दिए बिना पास किया गया था। आयुक्त का पास किया गया आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि वाद के किसी भी गुणदोष पर विचार नहीं किया गया और इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि इस पर ज़ोर नहीं दिया गया था।

12. दूसरी तरफ, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि एक बार उपप्रभागीय अधिकारी का पास किया गया आदेश वापस ले लिया गया है, तो कोई कार्रवाई की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुक्त के आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनी बात नहीं है और यह सही और वैध है।

13. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

14. आयुक्त के 07.04.2006 के आदेश को देखने पर, यह साफ़ है कि याचिकाकर्ता की खारिज करने की अर्जी में पुनरीक्षण को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उस पर ज़ोर नहीं दिया गया था, इसलिए, चक के पुनः आवंटन का आगे का आदेश पूरी तरह से गलत और गैर-ज़रूरी है। आयुक्त का आदेश पक्षों को सुने बिना और सुनवाई का मौका दिए बिना पास किया गया है, इसलिए, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की दलील का कोई मतलब नहीं है और उसे खारिज किया जाता है।

15. ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों और बताए गए कारणों को देखते हुए, 07.04.2006 के आक्षेपित आदेश का वह हिस्सा, जिसमें चक को दोबारा आवंटन करने का आदेश दिया गया था, साफ़ तौर पर गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाता है।

16. रिट याचिका सफल होती है और उसे स्वीकार किया जाता है ।

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

17 मार्च, 2026
आदर्श के सिंह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।